Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 20 , 11 अक्टुबर, बुधवार 2017, सूरत, **हिन्दी दैनिक** 9879141480

4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

नहीं थम रहा मौत का तांडव,9 नवजात समेत 14 की मौत

गोरखपुर। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज के बालरोग विभाग में मरीजों की मौत का सिलसिला कम नहीं हो रहा है। बीते 24 घंटे में विभाग में भर्ती 14 मरीजों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा नौ नवजातों की मौत शिशु गहन चिकित्सा कक्ष (एनआईसीयू) में हुई। जबकि पांच मरीजों की मौत इंसेफेलाइटिस व दूसरे अन्य बीमारियों से हुई। बीआरडी में इंसेफेलाइटिस से मरीजों की मौत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। बीते 48 घंटे में इस बीमारी से आठ मरीजों की मौत हो गई। इसके साथ ही इस साल मौतों का आंकड़ा बढ़कर 318 हो गया। मरने वालों में देवरिया के धीरज, बस्ती की अमिका, महराजगंज के जैनभ व निजा, कुशीनगर के लकी, गुंजा व अंगद और बिहार के रोहित कुमार शामिल हैं। इस समय इंसेफेलाइटिस वार्ड में 104 मरीजों का इलाज चल रहा है। मासूमों पर मौत का कहर, गोरखपुर के आसपास के जिलों में 277 जानें गईं।

यूपी-100 में भरे जाएंगे 4493 पद, बंपर नौकरी का मौका

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने 'यूपी 100' परियोजना को सफ्लतापूर्वक संचालित करने के लिए 4493 नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है। इसमें सबसे ज्यादा 3000 पद आरक्षी चालक के हैं। गृह सचिव भगवान स्वरूप द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार इन पदों की मांग का प्रस्ताव वर्ष 2016 में ही तत्कालीन डीजीपी ने भेजा था। इंस्पेक्टर (मिनिस्टीरियल) के 18, सब इंस्पेक्टर (मिनिस्टीरियल) के 75, मुख्य आरक्षी चालक के 1400 तथा आरक्षी चालक के 3000 पदों पर भर्ती मंजूर हुई है। इंस्पेक्टर का वेतनमान 44900-138300, सब इंस्पेक्टर का 35400-109100, मुख्य आरक्षी चालक का 25500-78700 तथा आरक्षी चालक का 21700-67100 रुपये होगा।

सुप्रीम कोर्ट से सरकार ने कहा, अगर मंजूरी दी तो होगा दुरुपयोग

नई दिल्ली। इच्छामृत्यु के मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इसका विरोध किया है। आपको बता दें कि एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जिस तरह नागरिकों को जीने का अधिकार दिया गया है उसी तरह उसे मरने का भी अधिकार है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ के समक्ष केन्द्र सरकार ने कहा कि अगर इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी गई तो इसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है। इस बेंच में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस एके सिकरी, एएम खानविलकर, डीवाई चंद्रचूड़ और अशोक भवन भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी।आपको बता दे कि फरवरी 2014 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें एक गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति जो कि डॉक्टर्स के मुताबिक अब कभी ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए इच्छामृत्यु या दया मृत्यु की अपील की गई थी। कोर्ट में याचिका लगाने वाली एनजीओ ने दलीली दी कि 'गरिमा के साथ मरने का अधिकार' 'यानी राइट टू डाय विथ डिग्निटी' भी होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 25 फरवरी, 2015 को यह मामला संविधान पीठ के पास भेज दिया था। इसके अलावा संविधान पीठ कल्पना मेहता बनाम भारत सरकार, स्टेट ऑफ झारखंड बनाम हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम पुष्पा और अन्य से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही है।

कांग्रेस नेताओं का अय्यर पर जमकर हमला

नई दिल्ली। ऑल इंडिया वाल्मीकि यूथ फ्रंट के कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने मणिशंकर अय्यर पर जमकर प्रहार किया। नेताओं का कहना था कि अय्यर को कांग्रेस ने हमेशा सम्मान दिया, केन्द्र में मंत्री बनाया वही अब कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर हमले कर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। शाह ऑडिटोरियम में फ्रंट का यह कार्यक्रम वाल्मीकि जयंती पर चौधरी सरपंच कमेटी से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं के सम्मान में आयोजित था। इस अवसर पर पूर्व विधायक जयकिशन ने मणिशंकर अय्यर के बयान की निंदा करते हुए कहा कि अय्यर का व्यवहार, पार्टी के प्रति सोच और कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के प्रति भावनाएं उजागर हो गई।

सात विकास कार्यों का लोकार्पण और पांच योजनाओं का शिलान्यास करेंगे।

मिशन अमेठी: इन जगहों का दौरा करेंगे अमित शाह,

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को लखनऊ, सीतापुर और अमेठी के प्रवास पर रहेंगे। वे सबेरे 10 बजे चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ से हेलीकाप्टर से सबेरे 11 बजे सम्राट साइकिल फैक्ट्री ग्राउन्ड अमेठी पहुंचेगे। वहां वे केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी व मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के साथ एक जनसभा करेंगे। इसके साथ ही सात विकास कार्यों का लोकार्पण और पांच योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बाद में शाह दोपहर डेढ़ बजे सीतापुर पहुंच कर वहां से पार्टी के 51 जिला कार्यालयों की आधारशिला रखेंगे। शाम को लखनऊ पहुंच कर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित पांच सरसंघ चालकों के कृतित्व पर रचित पुस्तकों का सांइटिफिक कन्वेशन सेंटर में विमोचन करेंगे। इसके बाद रात में वापस दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अमेठी में जनसभा के साथ करेंगे विकास कामों का लोकार्पण-शिलान्यास करेंगे। अमेठी में शाह राजकीय क्षयरोग औषधालय गौरीगंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ओवारी बहादुरपुर, स्वास्थ्य केन्द्र करथुनी मुसाफिरखाना, अमेठी व शाहगढ़ व भादर विकास खण्ड के रोगी आश्रय स्थल,अमेठी विकास खण्ड में सीएचसी का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा सीएमओ आवास व कार्यालय, अमेठी संसदीय क्षेत्र के तहत सुल्तानपुर स्थित गोमती नदी के किनारे पर 1990 लॉंचिग एप्रन, गौरीगंज के एफ़एम रेडियो, अमेठी कलेक्ट्रेट के आवासीय-अनावसीय भवन तथा मृदा परीक्षण प्रयोशाला का शिलान्यास करेंगे। सीतापुर में करेंगे 51 भाजपा कार्यालयों के भवनों का शिलान्यासभाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमेठी में जनसभा व विकास परियोजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास करने के बाद हेलीकॉप्टर से सीतापुर जाएंगे। जहां वे सीतापुर समेत आजमगढ़, बहराइच, देवरिया, एटा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, मथुरा, संतकबीर नगर, गोरखपुर, हापुड़, भदोही, कन्नौज, बुलंदशहर, श्रावस्ती, बांदा, महोबा, हाथरस, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, बरेली, इलाहाबाद, मैनपुरी, कासगंज, उन्नाव, सिद्धार्थनगर, सम्भल, गाजीपुर, वाराणसी, अमेठी, बदांयू, कानपुर देहात, इटावा, रामपुर, औरैया, अम्बेडकरनगर, सोनभद्र, गोण्डा, मेरठ, हरदोई, कौशाम्बी, फैजाबाद, फिरोजाबाद, लखीमपुर, सीतापुर, चंदौली, जेपीनगर, प्रतापगढ़ तथा मुरादाबाद के जिला पार्टी कार्यालयों के भवनों की आधारशिला रखेंगे।

लखनऊ में आरएसएस की पुस्तकों का विमोचन करेंगे

इसके बाद शाम को वे लखनऊ आ जाएंगे। यहां आकर वे 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पांच सरसंघचालक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केन्द्रित पुस्तकों का शाम पांच बजे लोकार्पण साइन्टिफिक कन्वेंशन सेंटर चौक में करेंगे।

इसके बाद उनके भाजपा प्रदेश मुख्यालय आकर पदाधिकारियों के साथ बैठक करने की भी संभावना है। जिन पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे उनमें प्रमुख रूप से हमारे डा. हेडगेवारजी, हमारे श्री गुरुजी, हमारे बाला साहब देवरस, हमारे रज्जू भैया और हमारे सुदर्शन जी किताबें शामिल हैं।

मिशन 2019: शाह का हमला

कांग्रेस ने 3 पीढ़ी तक अमेठी का विकास नहीं किया

अमेठी। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को बीजेपी ब्रिगेड लेकर अमेठी पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही उन्होंने मिशन 2019 का नारा दिया।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में अमेठी का कोई विकास नहीं हुआ है, लेकिन साल 2019 में हम काम और विकास के नाम पर जीत हासिल करेंगे। उनके साथ मंच पर योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी भी थीं।

शाह ने कहा स्मृति ने लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी यहां से रिश्ता नहीं तोड़ाष उन्होंने कहा कि 3 पीढ़ी से अमेठी का नेतृत्व करने के बाद भी कांग्रेस ने विकास नहीं किया। विकास के दो मॉडल होते हैं, एक मोदी मॉडल एक कांग्रेस मॉडल। उन्होंने गुजरात व यूपी के विकास की तुलना करते हुए कहा कि जल्द ही यूपी में संपूर्ण विकास होगा।

कांग्रेस के गढ़ में भाजपा: स्मृति बोलीं, 2019 में भी खिलेगा कमल

इससे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन की शुरुआत वंदेमातरम से की। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष का पहला अमेठी आगमन है। स्मृति को अमेठी के विकास के लिए संघर्षरत बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार विकास में कोई कोर कसर नही छोड़ेगी। योगी ने कहा कि मोदी ने देश विदेश में भारत का मान बढ़ाया।

लखनऊ में आरएसएस की पुस्तकों का विमोचन करेंगे

आज शाम को वे लखनऊ आ जाएंगे। यहां आकर वे 'राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पांच सरसंघचालक के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर केन्द्रित पुस्तकों का शाम पांच बजे लोकार्पण साइन्टिफिक कन्वेंशन सेंटर चौक में करेंगे। इसके बाद उनके भाजपा प्रदेश मुख्यालय आकर पदाधिकारियों के साथ बैठक करने की भी संभावना है।

जिन पुस्तकों का लोकार्पण करेंगे उनमें प्रमुख रूप से हमारे डा. हेडगेवारजी, हमारे श्री गुरुजी, हमारे बाला साहब देवरस, हमारे रज्जू भैया और हमारे सुदर्शन जी किताबें शामिल हैं।

यूपी के कर्मचारियों को मिलेगा बोनस, आज लगेगी मुहर

लखनऊ। दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को बोनस मिल जाएगा। बोनस से संबंधित फाइल सोमवार को वित्त विभाग से मुख्य सचिव के पास भेजी गई। मुख्य सचिव से होते हुए यह फाइल मुख्यमंत्री के पास जाएगी। मुख्यमंत्री की मुहर लगते ही बोनस देने का फरमान जारी हो जाएगा। 30 दिन का बोनस देने का फैसला हुआ है।

लगभग 7 हजार मिलेंगे

वित्त विभाग ने करीब 14 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की फाइल तैयार की है। बोनस का लाभ अराजपत्रित राज्य कर्मचारी जिसमें निकाय कर्मी भी शामिल हैं, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षक, शिक्षणोतर कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को मिलना है। वर्ष 2016-17 के लिए यह बोनस मिलेगा। प्रत्येक कर्मचारी को करीब सात हजार रुपये बोनस के रूप में मिलेंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 1184 रुपये बोनस का भुगतान होगा। 4800 ग्रेड पे वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा।
वहीं इसी ग्रेड पे के राजपत्रित अधिकारियों को बोनस नहीं मिलेगा। तय बोनस की 758धनराशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगी। शेष 25 फीसदी धनराशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं है उनके मामले में बोनस की 758 धनराशि उनके पीपीएफ खाते या एनएससी में जाएगी। इस बीच, उत्तर प्रदेश सचिवालय संघ के अध्यक्षयादवेंद्र मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार दीपावली से पूर्व बोनस देना सुनिश्चित करे। मुख्यमंत्री के स्तर से शीघ्र ही बोनस देने का आदेश हो जाने की उम्मीद है। समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्र के तौर पर पढ़ा रहे शिक्षामित्रों को अगस्त-सितम्बर का मानदेय जल्द मिलेगा। सर्वशिक्षा अभियान ने शिक्षामित्रों के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय की धनराशि जारी कर दी है।
एक अगस्त से 1.70 लाख शिक्षामित्रों को मानदेय दिया जाएगा। गैर समायोजित शिक्षामित्रों के लिए भी अतिरिक्त धनराशि जारी की गई है। प्राइमरी स्कूलों में 26,504 शिक्षामित्र गैर समायोजित थे। अभी तक उन्हें 3500 रुपये मानदेय दिया जाता था।

यूपी के 20 लाख युवा डिप्रेशन के शिकार,ये है वजह

मेंटल हेल्थ सर्वे:

कानपुर। बड़े-बड़े सपने लेकर जिंदगी की शुरुआत करने वाले युवा जब हकीकत की बेरहम जमीन पर खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो उसके अंदर हताशा घर करने लगती है। हताशा की ऐसी ही कई स्वनिर्मित वजहों के चलते प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा हताशा की प्रवृत्ति का शिकार हो रहे हैं। यह हताशा उन्हें नशे की लत में धकेलने से लेकर जिंदगी से मोहभंग तक खींच ले जा रही है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेंटल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट में ऐसा ही एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सैंपल सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा कामकाजी युवाओं में जिंदगी जीने का हौसला घट गया है। यह संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज में आयोजित तीन दिवसीय भारतीय साइकियाट्रिक सोसाइटी सेंट्रल जोन के वार्षिक अधिवेशन में इस रिपोर्ट पर चर्चा की गई। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रदेश के 1.95 करोड़ लोग किसी न किसी तरह की मानसिक बीमारी का शिकार हैं। यह रिपोर्ट प्रदेश के कुछ जिलों में सैम्पल सर्वे के आधार पर तैयार की गई है। संगठन के सेंट्रल जोन के नवनियुक्त चेयरमैन डॉ. रवि कुमार के मुताबिक रिपोर्ट भयावह स्थित दर्शाती है। ओपीडी में आने वाले लगभग 95 फीसदी मरीज डिप्रेशन के किसी न किसी स्टेज में हैं। यह समस्या शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बढ़ रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कुछ अधिक है। युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी, किसी न किसी तरह के नशे की प्रवृति के चलते डिप्रेशन के साथ ही मूड डिसआर्डर जैसी गम्भीर बीमारियां बढ़ा रही हैं।

हताशा के पांच कारण

-अपेक्षा के अनुरूप नौकरी या काम न मिलना

-काबिलियत के अनुसार वेतन न मिलना

-निजी और सरकारी दोनों में ही असुरक्षा की भावना

-जरा-सी विपरीत स्थिति में नशे की गिरफ्त में आ जाना

-बड़े-बड़े सपने देखना और हकीकत का विपरीत होना

ये उपाय बचा सकते हैं

-तनाव महसूस हो तो व्यायाम और योग करें

-अपने संसाधन और क्षमता के अनुरूप ही काम करें

-सकारात्मक विचारों से बेहतरी की उम्मीद बढ़ाएं जहां भी अच्छे काम हो रहे हों वहां जरूर जाएं

-बिना लापरवाही मनोचिकित्सक की सलाह लें

सरकार से अपेक्षाएं

जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम को मजबूत करने के साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर मनोविशेषज्ञों की तैनाती व दवाओं का समुचित प्रबंध किया जाना चाहिए। पुणे से आए बिग्रेडियर डॉ. एमएसवीके राजू के मुताबिक एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में मनोरोग विषय शामिल किया जाना चाहिए। एमडी की सीटें देश के मेडिकल कॉलेजों में बढ़ें।

मनोरोग विशेषज्ञों की कमी के कुछ आंकड़े

-6000 विशेषज्ञ 130 करोड़ की जनसंख्या पर देश में

-50000 विशेषज्ञ 30 करोड़ की जनसंख्या में अमेरिका में

-75 प्रतिशत मनोरोगियों को मिल पाता है इलाज

-20 लेक्चरर हैं मनोरोग पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में

-01 महीने साइकियाट्री की ट्रेनिंग एमबीबीएस पाठ्यक्रम में

-15 दिन इंटर्नशिप एमबीबीएस की मनोरोग विभाग में

लखनऊ रूट पर मगरवारा के पास ट्रैक फ्रैक्चर, एक घंटे ठप रहा संचालन

कानपुर। कानपुर-लखनऊ रेलमार्ग पर स्थित गंगाघाट-मगरवारा स्टेशनों के बीच मंगलवार को तड़के फ्रैक्चर हो गया। गैंगमैन की निगाह पेट्रोलंग के दौरान ट्रैक पर पड़ी तो तत्काल कंट्रोल के जरिए अफसरों को सूचना दी गई। रेलवे की इंजीनियरिंग टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर पटरी बदलने का काम शुरू किया। लगभग एक घंटे बाद ट्रैक ठीक हुआ, तब जाकर ट्रेन संचालन शुरू हो सका। इस चक्कर में मालगाड़ी, चित्रकूट एक्सप्रेस सहित आधा दर्जन ट्रेनें फंसी रहीं। सुबह-सुबह ट्रेनों की लेटलतीफी से दैनिक यात्रियों को खासी दिक्कतें झेलनी पड़ीं।

मंगलवार को सुबह पौने सात बजे लाइनमैन ट्रैक की पेट्रोलिंग कर रहा था, तभी गंगाघाट के आगे और मगरवारा के पहले ट्रैक में दरार दिखी। इसके बाद उसने सूचना दी।

डाउन मार्ग पर ब्लॉक होने की वजह से कानपुर से जाने वाली ट्रेनों को आउटर और गंगाघाट स्टेशन पर रोकना पड़ा। सुबह का समय होने की वजह से दैनिक यात्रियों को दिक्कतें हुई क्योंकि मेमू, मालगाड़ी, चित्रकूट एक्सप्रेस सहित छह ट्रेनों को रास्ते में रोकना पड़ा।

9वीं की छात्रा की हत्या कर युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर दी जान

वाराणसी। वाराणसी-भदोही बार्डर पर स्थित कपसेठी थाना क्षेत्र के घोसिला गांव में मंगलवार सुबह 9 बजे छात्रा की हत्या कर दी गई। कुछ दूरी पर एक युवक का शव भी रेलवे लाइन पर मिला- राहगीरों ने लाश देखी तो इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक और छात्रा का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार युवक व युवती दोनों एक ही बस्ती के हैं और अगल-बगल उनके मकान हैं- आशंका जतायी कि युवक ने पहले छात्रा की धारदार हथियार से हत्या की, फिर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने कुछ दूरी पर फेके गए हथियार को बरामद कर लिया है-

छात्रा का नाम अंजलि है और वह सेवापुरी स्थित कस्तूरबा महिला इंटर कॉलेज में कक्षा नौ में पढ़ती थी। परीक्षा होने की वजह से वह सुबह 8 बजे स्कूल के लिए निकली थी।

नवादा रेलवे लाइन के किनारे झाड़ियों में उसका शव मिला। वहीं 2 सौ मीटर दूर युवक आकाश का शव कटा हुआ मिला। इसकी सूचना जैसे ही गांव वालों को मिली हड़कम्प मच गया। मौके पर थानाध्यक्ष और सीओ पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस के अनुसार आकाश ने धारदार हथियार से पहले अंजलि की हत्या की। इसके बाद उसने कुछ दूर जाकर ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

चाचा-भतीजी का था रिश्ता

अंजलि और आकाश के बीच चाचा -भतीजी का रिश्ता था। आकाश का घर अंजलि के घर से कुछ ही दूरी पर था। लोगों की माने तो आकाश और अंजलि के बीच प्रेम संबंध था लेकिन अंजलि के परिवार वालों इस बात से इंकार कर दिया। उनका कहना था कि वह केवल पढ़ाई से मतलब रखती थी। घटना के बाद आकाश व अंजलि के परिवार वालों का रो-रो कर बुरा हाल है।

कम्प्यूटर कोर्स कर रहा था आकाश

परिवार वालों के अनुसार आकाश बीए में दो साल पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दिया था।

वर्तमान में वह कोई कम्प्यूटर का कोर्स कर रहा था। उसकी एक आंख खराब थी। आकाश के पिता मजदूरी करते हैं। वहीं उसके दो भाई भी है जो पढ़ाई कर रहे हैं।

लोगों के छिपे हुए ऐब जाहिर मत करो। इससे उनकी इज्जत तो जरूर घट जाएगी पर तुम्हारा तो ऐतबार ही उठ जाएगा -सादी

मेट्रो रेल का किराया

लगभग सभी समाजों में यह बात स्थापित है कि हमेशा सही और गलत के बीच ही विवाद और टकराव पैदा होते हैं, लेकिन वास्तविक अर्थो में यह सचाई के एक पहलू को ही बयान करता है। कभी-कभी समाज और राजनीति के दोनों विपरीत ध्रुवों के तर्क सचाईकी कसौटी पर सही और जायज उतरते हैं, लेकिन उनके बीच टकराव और मतभेद की स्थिति पैदा हो जाती है। दिल्ली मेट्रो रेल का किराया बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जारी टकराव इसकी बेहतर मिसाल है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का प्रबंधन और केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय मेट्रो को घाटे से उबारने के लिए भाड़ा बढ़ाने के पक्षधर हैं। जाहिर है कि किसी भी सार्वजनिक परिवहन का घाटा सरकार ज्यादा दिन तक वहन नहीं कर सकती। उसे स्वावलंबी बनना ही होगा, वरना पूरी व्यवस्था लचर होकर दम तोड़ देगी और सरकार के पास उसे बंद करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रहेगा। इसमें दो राय नहीं कि आज मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन बन गई है। इस बात पर गौर करते हुए दिल्ली मेट्रो रेल का लगातार विस्तार हो रहा है। यदि मेट्रो के यात्रियों को अच्छी सेवा और सुविधाएं मुहैया कराईजा रही हैं, तो किराया भी बढ़ाया जाना भी स्वाभाविक है। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में जन-कल्याणकारी सरकारों की अपने नागरिकों के प्रति भी कुछजवाबदेही बनती है। अलबत्ता, सरकारों की कोशिश रहती है कि सार्वजनिक परिवहन का भाड़ा न बढ़े क्योंकि आम आदमी ही ज्यादातर इसका इस्तेमाल करता है। लिहाजा, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी के पक्ष में खड़े होकर किराया बढ़ोतरी का विरोधकर रहे हैं। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते यह उनका लोकतांत्रिक कर्त्तव्य भी है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अक्सर जब केंद्र या राज्यों की सरकारें सार्वजनिक परिवहन या रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतें बढ़ाती हैं, तो विपक्षी पार्टियां उसका विरोधकरती हैं। कई बार विरोध के आगे सरकार को झुकना भी पड़ता है। इसलिए मेट्रो के किराया बढ़ोतरी के सवाल पर जारी विवाद को दो सही व्यक्तियों के बीच का टकराव के रूप में ही देखा जाना चाहिए। इस मसले पर मुख्यमंत्री केजरीवाल के प्रस्ताव का समर्थन किया जाना चाहिए, जिसके तहत घाटे की पूर्ति के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार को आधा-आधा रकम चुकाने का प्रस्ताव है। यह आम जनता के हक में है।

''हादसों का मंत्रालय'

रलवे सुधार की तरफअग्रसर है। हालिया हादसों के बाद नये-नवेले रेल मंत्री और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन देश के सबसे विशालकाय उपक्रम की अवसंरचना में सुधार के लिएजी-तोड़ प्रयास में जुटे हैं। इसी कड़ी में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे की कई कमजोर नसों में से एक वीआईपी कल्चर को खत्म करने की सिफारिश की है। साथ ही नया वर्क कल्चर लाने की दिशा में कदम उठाने का ऐलान भी किया है। ताजा फरमान के मुताबिक अब वरिष्ठ रेल अधिकारियों को घर और बाहर दोनों जगह काम करना होगा। साथ ही उन वरिष्ठ अधिकारियों की कोठियों में काम करने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को तुरंत रिलीव करने को कहा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेलवे में कर्मचारियों की तुलना में अधिकारियों की संख्या ज्यादा है। शायद रेल मंत्री को इसका संज्ञान है तभी उन्होंने इसे अमल में लाने का निर्णय लिया। वहीं एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए मंत्रालय ने 36 साल पुराने उस नियम को खत्म कर दिया, जिसमें रेलवे बोर्ड के चेयरमैन या अन्य बोर्ड सदस्य के जोनल दौरे के वक्त जनरल मैनेजर का खुद उनके आगमन या प्रस्थान के समय मौजूद रहना अनिवार्य था। इसके अलावा और भी कई फैसले वीआईपी कल्चर को खत्म करने के मकसद से लिये गए हैं। लेकिन लाख टके का सवाल यही कि क्या इस कवायद से संरक्षा और सुरक्षा- जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत रेलवे को है-उसे सही दिशा मिल सकेगी? क्योंकि जिस तरह से हाल में रेल विभाग ''हादसों का मंत्रालय' के नाम से कुख्यात हो चुका है, उसे कैसे पटरी पर लाया जा सकेगा? वैसे भी रेलवे में क्रांतिकारी बदलाव के वास्ते सिर्फ वीआईपी कल्चर को खत्म करने से कुछ खास हासिल नहीं होगा। इसके लिए कुछ सख्त फैसले भी लेने होंगे। मसलन, रेलवे को निर्माण कंपनी की तरफलौटना होगा, आऊट सोर्सिंग के चलन को खत्म या कम करना होगा, गुणवत्ता पर जोर देना होगा, रिटायरमेंट से खाली हो रहे कारखानों में नियुक्तियों को प्राथमिकता में लानी होगी वगैरह-वगैरह। यानी विभाग को कंपनीकरण की तरफ लौटना होगा, जिससे इसे वाणिज्यिक और सामाजिक रूप से लाभप्रद और सक्षम बनाया जा सके।

सत्संग

सम्मोहन

आप ध्यान कह रहे हैं, उसमें और आटो-हिप्नोसिस में, आत्म-सम्मोहन में क्या फर्क है? वही फर्क है, जो नींद और ध्यान में है। नींद है प्राकृतिक रूप से आई हुई और आत्म-सम्मोहन भी निद्रा है प्रयत्न से लाई हुई। हिप्नोसिस में-हिप्नोस का मतलब भी नींद होता है-हिप्नोसिस का मतलब ही होता है तंद्रा, उसका मतलब होता है सम्मोहन। तब एक आदमी लेट कर सोचे कि नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है..मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं सो रहा हूं..तो यह भाव उसके प्राणों में घूम जाए, घूम जाए, घूम जाए, उसका मन पकड़ ले कि मैं सो रहा हूं, नींद आ रही है, तो शरीर उसी तरह का व्यवहार करना शुरू कर देगा। कहेगा कि नींद आ रही है, शिथिल हो जाओ। श्वासें कहेंगी कि शिथिल हो जाओ। मन कहेगा कि चुप हो जाओ। नींद आ रही है, इसका वातावरण पैदा कर दिया जाए भीतर तो शरीर उसी तरह व्यवहार करने लगेगा। शरीर तो बहुत आज्ञाकारी है। आपको रोज ग्यारह बजे भूख लगती है, आप खाना खाते हैं ग्यारह बजे और आज घड़ी में चाबी नहीं भर पाए हैं और घड़ी रात में ही ग्यारह बजे रु क गई है और अभी सुबह के आठ ही बजे हैं, और आपने देखी घड़ी और देखा कि ग्यारह बज गए हैं, एकदम पेट कहेगा कि भूख लग आई। अभी ग्यारह बजे नहीं हैं, अभी तीन घंटे हैं बजने में। लेकिन घड़ी कह रही है कि ग्यारह बज गए हैं, पेट एकदम से खबर कर देगा कि भूख लग आई है क्योंकि पेट की तो यांत्रिक व्यवस्था है। रोज रात बारह बजे आप सोते हैं और अभी दस ही बजे हैं और घड़ी ने बारह के घंटे बजा दिए, घड़ी के घंटे देखकर आप फौरन पाएंगे कि तंद्रा उतरनी शुरू हो गई क्योंकि शरीर कहेगा कि बारह बज गए, अब सो जाना चाहिए। शरीर बहुत आज्ञाकारी है, जितना स्वस्थ होगा, उतना ही आज्ञाकारी होगा। स्वस्थ शरीर का मतलब ही है, आज्ञाकारी शरीर। अस्वस्थ शरीर का मतलब होता है, जिसने आज्ञा मानना छोड़ दिया। आप कहते हैं, नींद आ रही है; वह कहता है, कहां आ रही है। आप कहते हैं, भूख लगी है; वह कहता है, बिल्कुल नहीं लगी। आज्ञा छोड़ दे तो वह शरीर अस्वस्थ हो जाता है। आज्ञा मान ले तो स्वस्थ। क्योंकि वह हमारे अनुकूल चलता है, छाया की तरह अनुगमन करता है। जब आज्ञा छोड़ देता है, तो मुश्किल खड़ी हो जाती है। तो हिप्नोसिस का मतलब, सम्मोहन का मतलब इतना है कि शरीर को आज्ञा देनी है, और उसको आज्ञा में ले आना है।

''मेक इन इंडिया'

सरकार तात्कालिक परिवेश में अर्थव्यवस्था में गिरावट थामने के लिए औद्योगिक विकास, रोजगार और निवेश बढ़ाने के उपाय जारी रखेगी। छह अक्टूबर को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में भी राहतकारी बदलाव किए गए। इससे विकास दर बढ़ेगी और देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर आगे बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों नियंतण्र वित्तीय सेवा कंपनी मार्गन स्टेनली ने अपनी शोध अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि आगामी 10 वर्षो में भारत डिजिटलीकरण, युवा कौशल प्रशिक्षित आबादी और विभिन्न आर्थिक सुधारों की बदौलत दुनिया की सबसे तेज

सतीश पेडणोकर

इस समय राष्ट्रीय और नियंतण्र अध्ययन रिपोटरे में देश की विकास दर घटने के आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसे में 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के आधारभूत संकेतक मजबूत हैं। लेकिन सरकार तात्कालिक परिवेश में अर्थव्यवस्था में गिरावट थामने के लिए औद्योगिक विकास, रोजगार और निवेश बढ़ाने के उपाय जारी रखेगी। छह अक्टूबर को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में भी राहतकारी बदलाव किए गए। इससे विकास दर बढ़ेगी और देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर आगे बढ़ेगा।

पिछले दिनों नियंतण्र वित्तीय सेवा कंपनी मार्गन स्टेनली ने अपनी शोध अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि आगामी 10 वर्षो में भारत डिजिटलीकरण, युवा कौशल प्रशिक्षित आबादी और विभिन्न आर्थिक सुधारों की बदौलत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देगा। वर्ष 2027 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6000 अरब डॉलर के स्तर पर होगा और विकास दर करीब 11 फ ीसदी होगी। इसी तरह विश्वविख्यात ब्रिटिश ब्रोकरेज कंपनी हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन (एचएसबीसी) ने अपनी एक विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2028 तक भारत, जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी उसका क्रम दुनिया में पांचवां है। पहला और दूसरा क्रम क्रमश: अमेरिका और चीन का है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाहे वर्ष 2016-17 के पिछले साल के कुछ सुधारों से भारत की आर्थिक वृद्धि के रास्ते में बाधा उत्पन्न हुई है लेकिन कुछ समय बाद इन सुधारों से भारत की क्षमता का पूरा उपयोग होगा।

भारत को आर्थिक और कारोबार सुधारों के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना होगा, ऐसे सुधारों से 2018-19 के बाद अर्थव्यवस्था का प्रभावी रूप दिखाई देगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और विश्व बैंक की नियंतण्र आर्थिक विकास रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है। यद्यपि दुनिया की विभिन्न अध्ययन रिपोटरे में दस-बारह वर्ष बाद भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात एकमत से कही जा रही है।

यह सरल काम नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़े कई सकारात्मक पक्ष भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा भंडार और भारतीय रुपया अच्छी स्थिति में है। जीडीपी में प्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़ा है। फिर भी विकास दर घटने के परिदृश्य को बदलने और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को सतत आर्थिक-सामाजिक सुधार की जरूरत है। माहौल और तंत्र विकसित करना आवश्यक है। लेकिन सरकार को बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और सेवा क्षेत्र के योगदान का मौजूदा स्तर बढ़ाना होगा। रोजगार के अवसर पैदा करना होंगे। यह भी जरूरी है कि नोटबंदी और जीएसटी की शुरुआती दिक्कतों के कारण सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज पर विचार किया जाए। निश्चित रूप से अब अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अहम भूमिका बनाई जानी जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी की ''मेक इन इंडिया' योजना को गतिशील करना होगा। उन ढांचागत सुधारों पर जोर देना होगा जिससे निर्यातोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र को गति मिल सके। ऐसा किए जाने से भारत में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं आकार ग्रहण कर सकती हैं। पिछले दिनों विश्श्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर भारत चीन और पश्चिमी देशों को पीछे छोड़कर दुनिया का नया कारखाना बन सकता है।

यद्यपि इस समय दुनिया के कुल उत्पादन का 18.6 फीसदी उत्पादन अकेला चीन करता है। लेकिन कुछ वर्षो से चीन में लगातार सुस्ती एवं युवा कार्यशील आबादी में कमी और बढ़ती श्रम लागत के कारण चीन में औद्योगिक उत्पादन में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में उत्पादन गुणवत्ता के मामले में चीन से आगे चल रहे भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ने की अच्छी संभावनाएं मानी जा रही हैं।

नियंतण्र शोध संगठन स्टैटिस्टा और डालिया रिसर्च द्वारा मेड इन कंट्री इंडेक्स 2016 में उत्पादों की साख के अध्ययन के आधार पर कहा गया है कि गुणवत्ता के मामले में मेड इन इंडिया मेड इन चायना से आगे है। इस सव्रेक्षण के तहत लिए गए मानकों में उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा मानक, कीमत वसूली, विशिष्टता, डिजाइन, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, भरोसा, टिकाऊपन, सही उत्पादन और प्रतिष्ठा शामिल हैं। यूरोपीय संघ और दुनिया के 49 बड़े देशों को लेकर जारी इस इंडेक्स में उत्पादों की साख के मामले में चीन भारत से सात पायदान पीछे है।

प्रभावी मांग बढ़ाने और तेज विकास दर के लिए ऐसे प्रयास करने होंगे जिनसे आम आदमी की मुट्ठी में कुछ अधिक धन आए। उसकी क्रय क्षमता बढ़ जाए। महंगाई बढ़ाने वाले मध्यस्थों का दुष्चक्र रोकना होगा। सरकार द्वारा रोजगार बढ़ाने वाली विभिन्न योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सतत समीक्षा की जानी होगी। रोजगार सुरक्षा बढ़ाना होगी। इनके साथ-साथ श्रम सुधार, बैंकिंग सुधार और वित्तीय सुधार की डगर पर भी आगे बढ़ना होगा।

नई पीढ़ी को हमें नये आर्थिक माहौल के अनुरूप पल्लवित-पुष्पित करना होगा। आर्थिक स्थायित्व और विकास दर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षो में जो विभिन्न ऐतिहासिक नीतिगत फैसले लिए गए हैं, उन्हें शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वित करना होगा। साथ ही, संसद में पारित अभूतपूर्व आर्थिक सुधारों को कारगर तरीके से लागू किया जाना होगा। उम्मीद करें कि मोदी सरकार नीति आयोग के सुधारवादी एजेंडे को कार्यान्वित करने के लिए कारगर प्रयास करेगी। ऐसा होने पर निश्चित रूप से भारत अगले 10-12 वर्षो में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देगा।

चलते चलते

भारत-पाक मैच

कोई हल्ला, कोई चंचा, कोई मार्च, कोई मोमबत्ती, कोई टार्च नहीं। ये जो मुल्क है ना यह एक मुल्क सिर्फ भारत-पाक मैच के दौरान दिखाई देता है। वरना हरेक के अपने मुल्क अलग हैं। सीवर में डूबने वालों का मुल्क अलग है, कब कहां खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक टीवी पत्रकार ने ज्ञान दिया कि सीवर देखना कोई नहीं चाहता, जब तक वह हनीप्रीत का ही ना हो।

मबत्तियों, टीवी चैनलों की फितरत एक-सी है, कई मामलों में, ग्लैमर चाहिए होता है, ग्लैमर के बिना मोमबत्तियां इंडिया गेट की तरफ ना आतीं और टीवी चैनल खबर की तरफ ना आते। मार मची पड़ी है हनीप्रीत पर, सीवर में उतरे कई कर्मी वापस नहीं आए, वहीं जान निकल गई। कोई हल्ला, कोई चंचा, कोई मार्च, कोई मोमबत्ती, कोई टार्च नहीं। ये जो मुल्क है ना यह एक मुल्क सिर्फ भारत-पाक मैच के दौरान दिखाई देता है। वरना हरेक के अपने मुल्क अलग हैं। सीवर में डूबने वालों का मुल्क अलग है, कब कहां खो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। एक टीवी पत्रकार ने ज्ञान दिया कि सीवर देखना कोई नहीं चाहता, जब तक वह हनीप्रीत का ही ना हो। मैंने एक टीवी पत्रकार से कहा-भाई, दिखाओ तो कौन लोग जिम्मेदार हैं, सीवर में बिना सुरक्षा के बंदों को भेजने के लिए। टीवी पत्रकार ने जवाब दिया-हम प्रियंका चोपड़ा को दिखा सकते हैं, अगर वह सीवर की बात करें। कोई कंपनी अपने ब्रांड की स्पांसरशिप में कहीं शेर बचाने की मुहिम चला देती है, कहीं पर्यावरण बचाने की। पर सीवर में मर रहे इंसानों को बचाने की मुहिम में किसी को फायदा दिखाई नहीं पड़ता। कनाडा से टाईगर बचाने के लिए फंडिंग आती है, तो टाईगर बचाना ज्यादा फायदे का सौदा है, सीवर में मरने वाले इनसानों को बचाने की फंडिंग जब आने लगेगी, तब आप पाएंगे कि बड़े स्टार, बड़ी कंपनियां सीवर में मरते इनसान को बचाने में लग जाएंगे। दरअसल, कोई कुछ नहीं बचा रहा है, सब रकम बचा रहे हैं, उस रकम में जो भी लटक ले, वह बच सकता है। एक बड़े संपन्न एनजीओ के मित्र सड़क के आवारा कुत्तों तक को बचाने में जिंदगी दिए पड़े हैं क्योंकि आवारा कुत्तों के लिए फंडिंग आ रही है। फंडिंग आएतो विद्या बालन भी संवेदनशील हो जाएं सीवर में जाने वालों के लिए। थोड़ी ज्यादा फंडिंग आ जाए तो कैटरीना कैफतक को चिंतित करवाया जा सकता है सीवर में मरने वालों के कॉज के प्रति। फुक्के टाइप के कॉज को तो लोकल चैनल भी घास ना डालते, वो लेडीज क्लब का करवा-चौथ डांस दिखा देते हैं, जो भी हो, विज्युअली अपीलिंग होना चाहिए। सीवर की मौत विज्युअली-अपीलिंग कैसे हो-बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। है कोई एक्सपर्ट जो जवाब दे पाए।

मुद्दा

कराये वृद्धि का सिलसिला शुरू

रेल के किरायों खास तौर से देश की राजधानी दिल्ली में अरसे तक कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। सरकारें डरती रहीं कि किराये बढ़ाए तो जनता खिलाफ हो जाएगी। वोट मिलने में मुश्किल होगी। इधर किराये वृद्धि का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसा कि पांच महीने में दूसरी बार यात्रियों पर अच्छा-खासा बोझ डालने की तैयारी हो चुकी है। पिछली बार 10 मई को किराया बढ़ाया गया था, जिसके बाद जून में यात्रियों की रोजाना की संख्या में 1.66 लाख की कमी दर्ज की गई। अब 10 अक्टूबर से अधिकतम किराया 60 रुपये किया जाना तय है। मेट्रो रेल का किराया बढ़े या नहीं, इसके लिए कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एमएल मेहता की अध्यक्षता में पैनल बनाया था। इसके संदर्भ में असल में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने फेयर फिक्सेशन कमेटी (एफएफसी) का गठन किया था, जिसने मेट्रो किराया न्यूनतम 15 रुपये से अधिकतम 70 रुपये तक करने का प्रस्ताव किया था। इन सिफारिशों को मंजूर किया जाए या नहीं, इस पैनल को तय करना था। पहले भी कम से कम 5-6 बार किराये में बढ़ोतरी के लिए कमेटियों के गठन की सिफारिशें की गई पर हर बार चुनावी राजनीति के दबावों के तहत कैबिनेट ने ऐसे प्रस्ताव ठुकरा दिए थे। लेकिन फिलहाल दिल्ली के सामने चुनावों का कोई संकट नहीं है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने मेट्रो किराया बढ़ाने की मांग कई बार की है। उसका तर्क है कि स्थापना पर हुए खर्च की भरपाई और बढ़ते परिचालन खर्च के मद्देनजर ऐसा करना जरूरी हो गया है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2015-16 के बीच एक साल में दिल्ली मेट्रो को 275 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। रोजाना 27 से 30 लाख यात्रियों को ढोने वाली दिल्ली मेट्रो का घाटा आर्श्चयजनक ही है, ऐसे में व्यावसायिक नजरिया मेट्रो किराये में बढ़ोतरी का ही पक्ष लेता है। कहा जा सकता है कि कोई संगठन कुशलता के साथ कार्य संचालन कर रहा हो तो उसे पैसे की ऐसी तंगी नहीं आनी देनी चाहिए कि उसका संचालन ठप हो जाने की नौबत बन जाए। मेट्रो मैन ई श्रीधरन का कहना है कि मेट्रो का कुशल संचालन करना है, तो उसे प्राइवेट कंपनियों के हवाले करना होगा जो किराये तय करने का हक अपने हाथ में रखें। कोई भी प्राइवेट कंपनी इसमें पैसा नहीं लगाना चाहेगी क्योंकि इसमें मुनाफे की गुंजाइश नहीं है। निजी कंपनियां अपने निवेश पर 12-15 फीसदी का रिटर्न चाहती हैं, लेकिन आज तक किसी मेट्रो प्रोजेक्ट ने 2-3 प्रतिशत से ज्यादा रिटर्न नहीं दिया। इसमें कोई शक नहीं कि मेट्रो रेल भारत में सियासी झुनझुना बन गई है। दिल्ली में इसकी सफलता को देखकर लोगों ने इसे हर शहर की परिवहन व्यवस्था का सर्वोत्तम विकल्प मान लिया। राजनेताओं ने इसे जनता को खुश करने का एक बड़ा जरिया समझ आनन-फानन में कई राज्यों में इसके प्रोजेक्ट शुरू करवा दिए। बेशक, दिल्ली-मुंबई जैसे महानगरों में मेट्रो रेल की वजह से निवासियों का जीवन आरामदेह हुआ है। लेकिन ट्रॉम, बस आदि के मुकाबले चूंकि यह बेहद महंगा प्रोजेक्ट है, इसलिए हर बड़े शहर में मेट्रो रेल ट्रैक बिछा पाना हरेक राज्य के बूते की बात नहीं है। आज की तारीख में मेट्रो के लिए ट्रैक बिछाने की लागत 267 करोड़ रुपये प्रति किमी. को पार कर चुकी है सवाल है कि मेट्रो स्थापना और संचालन का खर्च जुटाने के लिए किराया बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है? सवाल मेट्रो के बढ़ते खर्च की भरपाई का है तो एक संतुलित नीति बनाई जा सकती है। किराये में मामूली (एक-दो प्रतिशत से पांच फीसदी तक) वृद्धि करने के साथ-साथ खर्च साधने के लिए उसे सब्सिडी दी जा सकती है। पर्यावरण और जनहित में कई देश ऐसा करते हैं। अमेरिका जैसे देशों में पर्यावरण हितैषी चीजों को सब्सिडी देकर जनता को उसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया जाता है। मिसाल के तौर पर लेड (सीसा) रहित पेट्रोल को वहां लागत से कम मूल्य पर बेचा जाता है। अच्छा होगा मेट्रो किराया बढ़ाने के बजाय उसके खर्चो पर दूसरे उपायों से नियंत्रण हो।

अभिव्यक्ति की हद!

आभा स्वामी

यकीनन, इस समय राष्ट्रीय और नियंतण्र अध्ययन रिपोटरे में देश की विकास दर घटने के आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं। ऐसे में 4 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अर्थव्यवस्था का विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए कहा कि अर्थव्यवस्था के आधारभूत संकेतक मजबूत हैं। लेकिन सरकार तात्कालिक परिवेश में अर्थव्यवस्था में गिरावट थामने के लिए औद्योगिक विकास, रोजगार और निवेश बढ़ाने के उपाय जारी रखेगी। छह अक्टूबर को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में भी राहतकारी बदलाव किए गए। इससे विकास दर बढ़ेगी और देश दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की डगर पर आगे बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों नियंतण्र वित्तीय सेवा कंपनी मार्गन स्टेनली ने अपनी शोध अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि आगामी 10 वर्षो में भारत डिजिटलीकरण, युवा कौशल प्रशिक्षित आबादी और विभिन्न आर्थिक सुधारों की बदौलत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार से बढ़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देगा। वर्ष 2027 तक भारत का सकल घरेलू उत्पाद 6000 अरब डॉलर के स्तर पर होगा और विकास दर करीब 11 फीसदी होगी। इसी तरह विश्वविख्यात ब्रिटिश ब्रोकरेज कंपनी हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन (एचएसबीसी) ने अपनी एक विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट में कहा है कि वर्ष 2028 तक भारत, जापान और जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी उसका क्रम दुनिया में पांचवां है। पहला और दूसरा क्रम क्रमश: अमेरिका और चीन का है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चाहे वर्ष 2016-17 के पिछले साल के कुछ सुधारों से भारत की आर्थिक वृद्धि के रास्ते में बाधा उत्पन्न हुई है लेकिन कुछ समय बाद इन सुधारों से भारत की क्षमता का पूरा उपयोग होगा। भारत को आर्थिक और कारोबार सुधारों के साथ-साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों की प्रक्रिया को निरंतर जारी रखना होगा, ऐसे सुधारों से 2018-19 के बाद अर्थव्यवस्था का प्रभावी रूप दिखाई देगा। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट और विश्व बैंक की नियंतण्र आर्थिक विकास रिपोर्ट में भी कहा गया है कि भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर सकता है। यद्यपि दुनिया की विभिन्न अध्ययन रिपोटरे में दस-बारह वर्ष बाद भारत के तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात एकमत से कही जा रही है। यह सरल काम नहीं है। लेकिन अर्थव्यवस्था से जुड़े कई सकारात्मक पक्ष भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। शेयर बाजार, विदेशी मुद्रा भंडार और भारतीय रुपया अच्छी स्थिति में है। प्रधानमंत्री मोदी की ''मेक इन इंडिया' योजना को गतिशील करना होगा। उन ढांचागत सुधारों पर जोर देना होगा जिससे निर्यातोन्मुखी विनिर्माण क्षेत्र को गति मिल सके। ऐसा किए जाने से भारत में आर्थिक एवं औद्योगिक विकास की संभावनाएं आकार ग्रहण कर सकती हैं। पिछले दिनों विश्श्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देकर भारत चीन और पश्चिमी देशों को पीछे छोड़कर दुनिया का नया कारखाना बन सकता है। यद्यपि इस समय दुनिया के कुल उत्पादन का 18.6 फीसदी उत्पादन अकेला चीन करता है। लेकिन कुछ वर्षो से चीन में लगातार सुस्ती एवं युवा कार्यशील आबादी में कमी और बढ़ती श्रम लागत के कारण चीन में औद्योगिक उत्पादन में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। यूरोपीय संघ और दुनिया के 49 बड़े देशों को लेकर जारी इस इंडेक्स में उत्पादों की साख के मामले में चीन भारत से सात पायदान पीछे है। मोदी सरकार नीति आयोग के सुधारवादी एजेंडे को कार्यान्वित करने के लिए कारगर प्रयास करेगी। ऐसा होने पर निश्चित रूप से भारत अगले 10-12 वर्षो में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाई देगा।

स्मृति का तंज, राहुल के पास अमेठी जाने का समय नहीं

अमेठी (ईएमएस)। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी के पास अमेठी की जनता के लिए समय नहीं है। हमारा लक्ष्य अमेठी के कोने-कोने तक विकास पहुंचाना है। स्मृति इरानी ने अमेठी से सांसद, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा कि उनके तथा भाजपा नेताओं के लगातार दौरों की वजह से राहुल का अमेठी में आना-जाना बढ़ा है और क्षेत्रीय जनता का अपने सांसद से मोहभंग हो रहा है।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा कपड़ा मंत्री स्मृति ने कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में कहा कि मैंने अमेठी और देश की जनता से वादा किया था कि मैं अमेठी का इतना ज्यादा दौरा करूंगी कि यहां की जनता राहुल गांधी को भी पहले के मुकाबले ज्यादा वक्त तक अपने बीच पाएगी। उन्होंने दावा किया कि राहुल का पिछले सप्ताह हुआ तीन दिवसीय अमेठी दौरा भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के आज के दौरे को देखते हुए ही तय किया गया था। स्मृति ने २०१४ के लोकसभा के चुनाव में अमेठी सीट से राहुल को कड़ी टक्कर दी थी, हालांकि वह जीत नहीं सकी थीं, लेकिन उन्हें मिले समर्थन की वजह से राहुल की जीत का अंतर वर्ष २००९ के लोकसभा चुनाव में तीन लाख ७० हजार मतों के मुकाबले भारी गिरावट के साथ एक लाख सात हजार वोट ही रह गया था। पराजय के बाद भी अमेठी में स्मृति की आमद-रफ्त जारी है और वह यहां विभिन्न विकास योजनाओं को धरातल पर उतारती नजर आयी हैं।

केन्द्रीय मंत्री ने एक पूर्व कांग्रेस विधायक तथा करीब ७० ग्राम प्रधानों के भाजपा में शामिल होने का जिक्र करते हुए कहा कि वे सभी अपनी उपेक्षा से नाराज थे। उन लोगों ने विकास की उम्मीद में कांग्रेस को समय दिया। उन्हें खासकर राहुल गांधी के नेतृत्व से आस थी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उपेक्षा और अपमान की वजह से अमेठी की जनता का राहुल से मोहभंग हो रहा है। इससे संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति पूरे देश को विकास के सब्जबाग दिखा रहा था, वह अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तक में विकास करने में नाकाम रहा। यह दिखाता है कि अगर अमेठी के लोग किसी दूसरी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, तो वह भाजपा ही है। केन्द्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांग्रेसनीत पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की योजनाओं का उद्घाटन किए जाने के राहुल के आरोप पर स्मृति ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष ने कहीं ना कहीं यह स्वीकार कर लिया है कि उन्हें सपने दिखाने की आदत है।

दस वर्षों में पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा से भागे 1199 अपराधी

लखनऊ (ईएमएस)। प्रदेश में कानून-व्यवस्था को धता बताते हुए पिछले 10 वषी में पुलिस व न्यायिक अभिरक्षा से 1,199 बंदी अपराधी फरार हो गये। अब पुलिस इन बंदी अपराधियों की तलाश कर रही है। प्रदेश के आईजी कानून-व्यवस्था हरीराम शर्मा ने यहां बताया कि राज्य के आठ जोनों आगरा, बरेली, इलाहाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर नगर, गोरखपुर और वाराणसी में फरार बंदियों के विरुद्ध आवश्यकतानुसार कार्यवाही की जा रही है। डीजीपी की ओर से जारी सूची के अनुसार 10 वषी में सबसे अधिक 196 अपराधी राजधानी लखनऊ से फरार हुए हैं और दूसरे नम्बर पर कानपुर नगर से 194 अपराधी फरार हुए हैं।

आगामी 18 अक्टूबर को अयोध्या में होगा दीपोत्सव का आयोजन

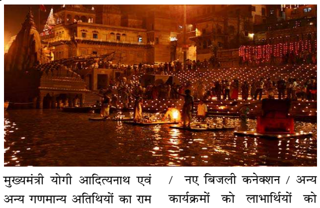

अयोध्या, फैजाबाद (ईएमएस)। आगामी 18 अक्टूबर को अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की उपस्थिति में भव्य दीपावली का आयोजन किया जाएगा। पूरी अयोध्या नगरी को सजाया जाएगा। इस कार्यक्रम के अनुसार प्रातकाल 07:00 बजे से 09:00 बजे तक कंचन भवन से नागेश्वरधाम मोक्षदायनी वाक में अयोध्या की हेरिटेज वाक कार्यक्रम का आयोजन होगा। तत्पश्चात अपराहन 02:00 बजे से 04:00 तक साकेत महाविद्यालय के सामने एकत्र होकर अयोध्या के मुख्य मागी से होकर राम कथा पार्क में समापन होगा जिसके अन्तर्गत राम के अयोध्या आगमन को दर्शाते हुए भव्य शाभ यात्रा प्रारम्भ होकर दो घण्टे के अन्तराल मे राम कथा पार्क पहुंचेगी। अपरान्ह 04:00 बजे राम कथा पार्क में महामहिम राज्यपाल राम नाईक, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं अन्य गणमान्य अतिथियों का राम कथा पार्क में अयोध्या में आगमन होगा। सायंकाल 04:00 बजे से 04:25 बजे तक राम कथा पार्क में ही शोभा यात्रा के राम कथा पार्क आगमन पर श्री राम जानकी का पूजन वन्दन / आरती, श्रीराम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक होगा।

तत्पश्चात 04:25 बजे से 04:55 बजे तक राम कथा पार्क में ही अयोध्या में हो रहे विकास कार्यों सम्बन्धी सभी विभागों की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना / नए बिजली कनेक्शन / अन्य कार्यक्रमों को लाभार्थियों को प्रतीकात्मक स्वीकृत पत्र वितरण / बच्चों को वस्त्र / मिष्ठान आदि का वितरण किया जाएगा। सायंकाल 04:55 बजे से 05:45 बजे तक विशिष्ठ अतिथियों का सम्बोधन / मा0 मुख्यमंत्री व महामहिम राज यपाल के आशीर्वाद वचन राम कथा पार्क में ही होगा।

तत्पश्चात सायंकाल 05:45 बजे से 06:00 बजे तक राम कथा पार्क के नए घाट पर प्रस्थान / विशिष्ठ अतिथियो को स्थान ग्रहण कराया जाएगा।

एनपीए कर्ज माफी के फैसले को भाजपा ने सराहा-भाजपा

लखनऊ (ईएमएस)। भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की सरकार के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें कर्ज में डूबे किसानों के एनपीए यानी नान परफारमिंग एसेट्स के कर्ज माफ कर दिए गए हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा है कि कैबिनेट के इस फैसले का सीधा फायदा करीब 13 लाख ऐसे किसानों को मिलेगा जो ना सिर्फ कर्ज में बुरी तरफ डूबे हुए थे बल्कि जिनके बैंक खातों को भी एनपीए की श्रेणी में डाल दिया गया था। ऐसे किसानों के खाता संचालन पर भी रोक थी और वे दुबारा कर्ज भी नहीं ले सकते थे। अब एनपीए की ऋण माफी के बाद ऐसे किसान ना सिर्फ खातों का संचालन कर पाएंगे बल्कि दुबारा खेती के लिए कर्ज भी ले सकेंगे। योगी सरकार के इस कदम से ऐसे 13 लाख किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिली है और किसानों के हित में इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

प्रदेश प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार पहले ही दिन से किसान हित में फैसले ले रही है। कर्ज माफी, रिकार्ड गेहूं खरीद और गन्ना भुगतान के बाद धान खरीद के बेहतर इंतजाम के जरिए किसानों को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की योजना सफलतापूर्वक काम कर रही है। श्री त्रिपाठी ने कहा कि एनपीए खाते वाले किसानों को तमाम तरह की विसंगतियों से जूझना पड़ रहा था। उनके खाते कुर्क थे और संपत्तियां कुर्क होने के कगार पर थीं। खेती के लिए नया कर्ज ना मिल पाने के चलते उनके लिए भविष्य की राह भी मुश्किल साबित हो रही थी। ऐसे में प्रदेश की भाजपा सरकार का ये फैसला ऐसे किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा।

बसपा प्रदेश में लोस उपचुनाव नहीं लड़ेगी

लखनऊ (ईएमएस)। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में होने वाला लोकसभा उपचुनाव न लड़ने का फैसला लिया है। लोकसभा उपचुनाव न लड़ने के फैसले की जानकारी पार्टी महासचिव सतीश चन्द मिश्र ने दी। श्री मिश्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही नही बल्कि पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर पछता रही है। भाजपा सरकारें महगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों को छोड़कर कुछ पूजीपतियों की झोली भरने में लगी हैं।

महिलाओं को अकेले हज पर जाने देने की सिफारिश पर बिफरे मौलाना

बरेली (ईएमएस)। हज के लिए महिलाओं के अकेले जाने देने की अनुमति देने से संबंधित केंद्र सरकार की सिफारिश की मौलानाओं ने तीखी आलोचना की है। सुन्नी बरेलवी धर्मगुरु ने इस कदम को गैर इस्लामिक करार दिया है। उनका कहना है कि महिलाओं को हज पर तभी जाने देना चाहिए, जब वे अपने किसी रक्त संबंधी पुरुष सदस्य के साथ हज पर जा रही हों। महिलाओं का अकेले हज जाना शरीयत के खिलाफ है। आला हजरत दरगाह के मौलाना मोहम्मद सलीम नूरी ने भी कहा कि महिलाएं अकेले हज जाएंगी, तो यह पाप होगा। उनका कहना है कि इस्लाम पांच स्तंभों पर टिका हुआ है। जिनमें से हज है। महिला मेहरम (करीबी पुरुष रक्त संबंध) के बिना हज करने नहीं जा सकती। महिलाओं को अकेले हज जाने देने की अनुमति के लिए एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अफजल अमानुल्ला ने केंद्र सरकार से अपील की थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने इस मसले पर गंभीर विचार किया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा हज कमिटी ऑफ इंडिया इस बारे में विचार कह रही है कि 45 वर्ष से ऊपर की महिला अगर अपने किसी करीबी पुरुष सदस्य के बिना ही हज जाना चाहती हैं तो उसे इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। दरअसल केंद्र सरकार ने शनिवार को नई हज नीति पेश की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करते हुए सब्सिडी की व्यवस्था खत्म करने और 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को बिना मेहरम के हज पर जाने की इजाजत देने का प्रस्ताव किया गया। हज नीति 2018-22 में हज यात्रियों को समुद्री मार्ग से भेजने के विकल्प पर काम करने की बात की गई। इसके तहत अब 45 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं बिना मेहरम के हज पर जा सकेंगी, हालांकि वे चार महिलाओं के समूह में जा सकेंगी। मेहरम के लिए कोटा 200 से बढ़ाकर 500 किए जाने का भी प्रस्ताव है। मेहरम उसे कहते हैं जिससे महिला का निकाह नहीं हो सकता। मसलन, पिता, सगा भाई, बेटा और पौत्र-नवासा मेहरम हो सकते हैं। आला हजरत दरगाह के मौलाना मोहम्मद सलीम नूरी ने भी कहा कि महिलाएं अकेले हज जाएंगी, तो यह पाप होगा। उनका कहना है कि इस्लाम पांच स्तंभों पर टिका हुआ है।

बिहार

मुझे शादी में तभी बुलाना जब दहेज नहीं लिया हो : नीतिश कुमार

दहेज प्रथा को लेकर सख्त सुशासन बाबू

पटना (ईएमएस)। बिहार में शराबबंदी का साहसिक निर्णय लेने वाले सुशासन बाबू ने समाज की दूसरी बुराई दहेज प्रथा को लेकर सख्त रुख कर लिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रित करने वालों को यह कहना होगा कि कोई दहेज नहीं लिया गया है। पटना में अपने आवास पर लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों द्वारा दहेज प्रथा एवं बाल विवाह को लेकर प्रदेश में छेड़े गए अभियान के बारे में पूछे जाने पर नीतीश ने कहा कि उन्हें विवाह समारोह में आमंत्रित करने पर कोई शपथपत्र नहीं मांगा जाएगा। लेकिन लोग यदि स्वयं यह कहेंगे कि मैंने बिना दहेज के शादी की है तो इसका समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा।''

उन्होंने समाज सुधार की दिशा में इसे बड़ा अभियान बताते हुए कहा कि इसमें आप मीडिया वाले भी इस अभियान को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। नीतीश ने कहा कि बिहार में बाल विवाह 39 प्रतिशत है। महिला अपराध में बिहार का 26वां स्थान है। यदि दहेज प्रथा एवं बाल विवाह बंद हो जायं तो कितना बड़ा बदलाव आयेगा। इसके लिए जागरूकता बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। अगले साल 21 जनवरी को मानव श्रृंखला बनेगी, जो जन समर्थन का प्रतीक होगी। लोग यदि खुद ही ये कहेंगे कि मैंने बिना दहेज के शादी की है तो इसका समाज पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया को समाज में बदलाव का बड़ा शक्तिशाली माध्यम बताया और उससे इस अभियान के सकारात्मक पहलू से लोगों को जागरूक करने का आह्वान किया। सुशासन बाबू का यह कदम खूब सराहा जा रहा है।

भागलपुर यूनिवर्सिटी में छात्र नेता ने किया आत्मदाह का प्रयास

भागलपुर। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर सोमवार को भी विश्वविद्यालय में छात्रों ने हंगामा किया। चुनाव के नामांकन फार्म फिर से भरवाने और छठ बाद चुनाव की मांग को लेकर रालोसपा के विश्वविद्यालय अध्यक्ष शिशिर रंजन ने प्रशासनिक भवन के नीचे अपने ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा ली।

लेकिन छात्रों ने उसे रोक लिया और पानी डालकर आग बुझा दिया। इस दौरान पूरी पुलिस फोर्स भी यहां लगी रही और आग बुझाने का प्रयास किया। घटना के बाद विभिन्न पार्टी के इन सभी छात्रों एवं छात्र नेताओं ने कुलपति आवास पर धरना दिया। यह सभी कुलपति आवास के बाहर बैठ गए हैं और वहां नारे लगा रहे हैं। इस दौरान सदर एसडीओ, डीएसपी, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष, स्पेशल ब्रांच के अधिकारी सहित पूरी फोर्स घटनास्थल पर तैनात है।

वरीय अधिकारी कुलपति से मिलने उनके आवास के अंदर गए हैं जहां पहले से इस मुद्दे पर बैठक चल रही है। वहीं दूसरी ओर यह छात्र 2 घंटे पहले जब मारवाड़ी कॉलेज में कॉलेज बंद कराने पहुंचे तो वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता चुनाव प्रचार कर रहे थे। जिसका विरोध अन्य पार्टी के छात्र नेताओं ने किया और इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई जिसमें एबीवीपी के 3 छात्रों को हल्की चोटें आईं। जो बाद में विश्वविद्यालय थाना पहुंचकर एफआईआर के लिए आवेदन दिए।

मधेपुरा के शंकरपुर में डायरिया का प्रकोप, एक की मौत

मधेपुरा। मधेपुरा के शंकरपुर में बेहरारी पंचायत के गुहिया टोला में डायरिया से एक युवती की मौत हो गई। गांव में चार दिनों के अंदर डायरिया से दो लोगों की मौत हो चुकी है। डायरिया का प्रकोप फैलने के बाद मेडिकल टीम गांव में कैंप कर मरीजों का इलाज कर रही है।

दूसरी ओर गिद्धा पंचायत के वार्ड 3 में भी डायरिया ने अपना पांव पसार दिया है। गिद्धा पंचायत में भी कई लोग डायरिया की च। जांच टीम के शिविर में सभी प्रभावित मरीज का इलाज चल रहा हैं। मालूम हो कि बेहरारी पंचायत के गुहिया टोला वाडं तीन में पिछले तीन दिनो डायरिया का प्रकोप जारी हैं जहां शुक्रवार को एक बच्चे का मौत भी डायरिया हो गया था।

दोनों टोला के डायरिया से पीड़ित 28 मरीजों का इलाज किया गया।

बिहार में चालक सिपाही के 700 पदों पर नौकरी

पटना। वाहन चलाने के अच्छी जानकारी रखने वाले युवक-युवतियों को एक बार फिर पुलिस में बहाल होने का मौका मिलेगा। राज्य सरकार चालक सिपाही के सात सौ पदों पर बहाली करने जा रही है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए अधियाचना भेज दी है। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को चालक सिपाही के पद पर बहाली की जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा।

अब लिखित परीक्षा भी देनी होगी चालक सिपाही पद के इकच्छुक अभ्यर्थियों को अब लिखित परीक्षा भी देनी होगी। पहले सिर्फ शारीरिक और वाहन चलाने की परीक्षा होती थी। बहाली के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत पहले लिखित परीक्षा होगी। हालांकि इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सिर्फ यह परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद ही अभ्यर्थी शारीरिक और फिर वाहन चलाने की परीक्षा में शामिल होंगे। पहले सिर्फ शारीरिक और वाहन चलाने की परीक्षा होती थी। बहाली के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत पहले लिखित परीक्षा होगी। हालांकि इसके आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार नहीं होगा।

इंटर पास होना अनिवार्य

चालक सिपाही के पद पर बहाली के लिए इंटर पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास हैवी (एचएमवी) या लाइट मोटर व्हैकिल (एलएमवी) चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। चालक सिपाही का वेतन एवं भत्ता बिहार पुलिस के सिपाही के समतुल्य है। पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए अधियाचना भेज दी है। केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) को चालक सिपाही के पद पर बहाली की जिम्मेदारी दी गई है। जल्द ही विज्ञापन निकाला जाएगा।

शरद राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं कर सकते: जदयू

पटना (ईएमएस)। जदयू ने विक्षुब्ध नेता शरद यादव द्वारा बुलाई गयी राष्ट्रीय परिषद की बैठक को अवैध करार देते हुए कहा कि उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं है। राज्यसभा सदस्य और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आर सी पी सिंह ने कहा कि शरद गुट के पार्टी नाम और प्रतीक चिन्ह के आवंटन की मांग को चुनाव आयोग द्वारा दो बार खारिज कर दिया। इसके मद्देनजर उन्हें पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के आयोजन का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा, 'मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि शरद यादव ने राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई थी। यह है पूरी तरह से अवैध है शरद यादव ने दावा किया है कि उनके द्वारा कल (नई दिल्ली में) बुलाई गयी राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ५००सदस्यों ने भाग लिया यह हकीकत से परे है। सिंह ने कहा कि शरद यादव ने जिस सूची का उल्लेख किया वह न केवल 'नकली' है बल्कि एक पुरानी सूची है। नवंबर २०१६ में राजगीर में नीतीश कुमार के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के साथ ऐसे लोगों का कार्यकाल २०१५ में समाप्त हो गया था। उन्होंने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि शरद ने उनके द्वारा बुलायी गयी बैठक में ५०० सदस्यों के भाग लेने का दावा किया है जबकि वर्तमान में राष्ट्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या १९४ ही है। सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद कुल १९४ सदस्यों में से सबसे बड़ी संख्या १०३ बिहार से, ३५ केरल से, ३१ झारखंड से, २३ जम्मू एवं कश्मीर से और २ दादर और नगर हवेली से है। प्रस्तावित सुविधाओं के लिहाज से यह बेहतर नीति है।

सीवान के महराजगंज में फिर से नहर का बांध टूटा, बाढ़ का खतरा बढ़ा

सीवान। सीवान के महराजगंज में फिर से नहर का बांध टूट गया है। इससे रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया और बाढ़ की आशंका बढ़ गई। अनुमंडल मुख्यालय के नजदीक से गुजर रहा गंडकी नहर का बांध एक बार फिर रविवार रात 12 बजे के आसपास टूट गया। इससे प्रखंड कार्यालय के अलावा आसपास के रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए।

चारों तरफ बाढ़ का नजारा दिखने लगा। पिछले दिनों भी इसी जगह नहर का बांध टूटा था। जिससे काफी क्षति हुई थी। हालांकि तब विभाग ने मरम्मत कराके नहर को सुरक्षति घोषित कर दिया। फिर उसी जगह बांध टूटने से विभाग की लापरवाही साफ नजर आती है। विभाग के कर्मी मौके पर पहुंच राहत व बांध की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है। बांध टूटने से प्रखंड कार्यालय, गंडक कॉलोनी व वन विभाग के परिसर में पानी जमा हो गया है। स्थानीय लोगों में विभाग के कर्मियों की लापरवाही को लेकर काफी आक्रोश है। जिससे काफी क्षति हुई थी। हालांकि तब विभाग ने मरम्मत कराके नहर को सुरक्षति घोषित कर दिया। फिर उसी जगह बांध टूटने से विभाग की लापरवाही साफ नजर आती है। विभाग के कर्मी मौके पर पहुंच राहत व बांध की मरम्मत का कार्य युद्धस्तर पर शुरू कर दिया है।

बिहार सरकार की सौगात, युवाओं को जल्द मिलेगा टैबलेट

लखनऊ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवाओं को राज्य सरकार टैबलेट देगी। इस योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य के युवाओं के कौशल विकास के लिए राज्य के प्रखंडों तक प्रशिक्षण केंद्र खोले गये हैं।

मुख्यमंत्री सोमवार को एक अणे मार्ग में लोक संवाद कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कुशल युवा कार्यक्रम के तहत युवाओं को कंप्यूटर और भाषा का ज्ञान, जिसमें अंग्रेजी बोलना भी शामिल है और व्यवहार कौशल की जानकारी दी जा रही है। ताकि वे कहीं भी नौकरी की तलाश में जाएं तो बेहतर ढंग से अपनी बात रख सकें। नौकरी खोजने में उन्हें सहूलियत हो। कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी भी उनके पास रहे। इसके लिए सभी प्रखंडों में प्रशिक्षण केंद्र बनाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छह अक्तूबर को केंद्रीय पेट्रोलियम सह कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना आए थे। उन्हें भी बिहार के कुशल युवा कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। उनके साथ मंत्रालय के अधिकारी भी थे। हमने आग्रह किया था कि वे कुशल युवा प्रशिक्षण केंद्र में जाकर देखें कि कैसे चल रहा है। आगे इस योजना को केंद्रीय योजना में शामिल करने पर विचार करें।

पेट्रोल-डीजल का आधार मूल्य घटाए केंद्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पेट्रोल-डीजल का आधार मूल्य कम करने का आग्रह हमने केंद्र से किया है। छह अक्तूबर को पटना आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी इस संबंध में बात हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में पेट्रोल का आधार मूल्य करीब 56 रुपये है। जबकि झारखंड में यह 51 रुपये है। कई राज्यों में आधार मूल्य बिहार से काफी कम है। इस पूरे आधार मूल्य को रिकैलकुलेट करने की जरूरत है।

बालू की किल्लत जल्द दूर होगी

मुख्यमंत्री ने कहा कि बालू के अवैध कारोबार को रोकने के लिए हमने कड़े कदम उठाये हैं। दो नंबर की कमाई करने वालों पर अंकुश लगी है। ये लोग पर्यावरण से खुलेआम खिलवाड़ करते थे।

केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया ने जीएसटी हुए सुधार से पत्रकारों को कराया अवगत

सूरत। रोड ट्रांसपोर्ट , हाईवेज, शिपिंग केमिकल्स तथा फर्टिलाइजर्स केंद्रीय मंत्री मनसुखभाई मांडविया ने मंगलवार को सूरत में जीएसटी में किए गए सुधार के संदर्भ में जानकारी देने के उद्देश्य से पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन नेशन वन टेक्स की संकल्पना को साकार करने की दिशा में सरकार सतत प्रयास कर रही है। जीएसटी को आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे शुरूआत में थोड़ी बहुत मुश्किले तो आएगी, परन्तु इसका दीर्घकालीन प्रभाव देखने को मिलेगा। सूरत शहर में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से जुड़े विविध संगठनों द्वारा जीएसटी की जटीलताओं को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं। जिसपर जीएसटी काउंसिल द्वारा गहन विचार करने के बाद इसमें आवश्यक सुधार किए गए हैं। सरकार ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेगी जिससे व्यापार को किसी प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़े। जीएसटी काउंसिल द्वारा किए गए संशोधनों पर जानकारी दी। इस अवसर पर सासंद सी.आर पाटील, तथा दर्शना बेन जरदोश ने भी जीएसटी पर अपना पक्ष रखा।

एम्पायर स्टेट में एकत्रित हुआ 65 यूनिट रक्त

सूरत। मानवता की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली संस्था महावीर इंटरनेशनल, न्यू सिविल हास्पीटल तथा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर न्यू सिविल हास्पीटल के सुपरिंटेंडेट डा. एम. के. वाडेल, महावीर इंटरनेशनल के चेयरमैन यशवंत सुराणा, सेकेट्री दिनेश जैन, मुकेश जैन, सुरेश गांधी, सुरेंद्र मारोथी, अनिल वर्डिया, राकेश श्रीमाल, डा. रोशन वाफना , संदीपजी, संजय अग्रवाल इत्यादि के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर सफलता पूर्वक सम्पन्न हुई। जिसमें कुल 65 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सुरेश गांधी ने बताया कि इस तरह की सेवा से दिल को काफी शकुन मिलता है। हर किसी को किसी न किसी प्रकार की सेवा के कार्य से जुड़े रहना चाहिए।

सूरत। काग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के गुजरात दौरे के विरोध में मंगलवार को शहर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओ ने भाजपा मुख्यालय के सम्मुख राहुल गांधी के विरोध में नारे लिखे हुए तक्तीयों का प्रदर्शन किया।

सूरत। फेडरेशन ऑफ टेक्सटाईल ट्रेडर्स के त्तवाधान में मंगलवार को फोस्टा के बोर्ड रूम में ट्रेफिक समस्या को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पधारे ट्रेफिक के डीसीपी ने व्याारियों को ट्रेफिक की समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया।

स्वच्छता के नाम पर फिस्डडी साबित हुई मनपा

सूरत। एक तरफ सूरत महानगर पालिका स्वच्छता के ढोल पीट रही है, तो दूसरी तरफ मनपा अधिकारियों की लापरवाही के चलते लोगों को गंदगी में जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। शहर के लाल दरवाजा विस्तार की हालत तो यही बया कर रही हैं। इस क्षेत्र में साफ सफाई के अभाव के कारण चारों तरफ गर्मी का साम्राज्य फैले होने के कारण पीछले एक महीने से यहां के निवासी डेंग्यू जैसी जान लेवा बीमारी की चपेट में आ गए है। मनपा का कोई अधिकारी यहां पर फरका नही है।बस यहां के स्तनिक नगर सेवक दिनेश काछड़िया ने पूरे मुद्दे को उठाया है ।जिन्होंने आरोग्य अशिकारी की स्थल पर मुलाका जिनकी किसी प्रकार की सुध मनपा अधिकारियों द्वारा नहीं ली जा रही है, जिससे स्थानीय जनता में मनपा अधिकारियों के विरुद्ध गहरा रोष व्याप्त है। लाल दरवाजा पटेल वाड़ी क्षेत्र में पिछले एक माह से डेंग्यू जैसी महामारी का कहर छाया है। यहां निवास करते लोगो को अस्पतालमे भी भर्ती करवाया गया है, और कई लोगो को डिस्पेंसरी में भी उपचार दिया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जोन कार्यालय में जाकर हम लोगों ने इस संदर्भ में कई बारे शिकायतें की हैं पर किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है। जब इसकी शिकायत क्षेत्र के पार्षद दिनेश काछड़िया के पास स्थानीय निवासियों द्वारा शिकायत करने पर उन्होंने तुरंत लाल दरवाजा पटेल वाड़ी की मुलाकात ली और तुरंत यहां पर साफ सफाई का कार्य शुरू करवाया। वही दूसरी और मनपा आरोग्य अधिकारी को भी पटेल वाड़ी बुलाकर मामले की गंभीरता का ब्यौरा दिया था। गौर तलब है कि सूरत महानगर पालिका साफ सूरत सुंदर सूरत के दावे करने से नही थकती तो दूसरी और लाल दरवाजा पटेल वाड़ी में पिछले एक महीने से बेसुमार गंदगी के कारण लोग डेंग्यू जैसी जानलेवा बीमारी के चंगुल में आ गए है। हालांकि स्थानीय कॉर्पोरेटर दिनेश काछड़िया द्वारा की गई पहल से पटेल वाड़ी क्षेत्रे में आंशिक परिवर्तन तो आया है मगर सूरत को साफ व सुंदर रखने का कार्य मनपा का है ना कि कॉर्पोरेटर का ।

सूरत। सूरत जिला सहकारी दुध उत्त्पादक संघ लि. के अध्यक्ष राजेश कुमार कांतीलाल पाठक तथा नियामक मंडल सदस्यों द्वारा मंगलवार को सूरत सुमूल डेरी में मास्टर सेफ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सुमूल के अलावा शहर के कई गणमान्य व्यक्ति उपसिथत रहे।

महाप्रभुनगर कारखाने में लगी आग से मची अफरा-तफरी

सूरत। गत रोज देर रात लिंबायत महाप्रभुनगर में स्थित टेक्सटाइल कारखाना में शोर्ट सर्किट से आग लग गई। जिसमें दूसरे मंजिले पर फंसे दो कारीगरों को सही-सुरक्षित बचा लिया गया। हलांकि आग से मशीनरी, वायरिंग और यार्न के जत्थे को भारी क्षति हुई। फायर विभाग के सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत रोज मध्यरात 12:44 बजे लिंबायत महाप्रभुनगर मधुनगर सोसायटी में प्लोट नंबर 62 में स्थित टेक्सटाइल कारखाने में आग लग गई। दूसरे मंजिले पर लगी आग में दो कारीगर फंस गये थे। घटना की जानकारी होते ही फायर ऑफिसर हार्दिक पटेल स्टाफ के साथ घटना स्थल पर पहुंच गये और आग को नियंत्रण में लेने के साथ दूसरे मंजिले पर फंसे कारीगरों को रेस्क्यु कर सही सुरक्षित बाहर निकाला।

सूरत। हजरत ख्खवाजा सैयद मोहम्मद देहदार साहेब नक्स बंधी रहमत तुल्ला अलय फिक्स मोहर्रम चांद के 30 वें हिसाब पर ऊर्स का आयोजन किया गया। 16वां चांद गुसल शरीफ, 17वां चांद संदल तथा 18वां चांद ऊर्स के रूप में मनाया जाएगा। मंगलवार को इस अवसर पर शहर के दरगाह शरीफ को विविध प्रकार की रंगबिरंगी रोशनियों से सजाया गया। इस अवसर पर कव्वाली का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में गादीनशीन सैयद अमीना बेगम, सैयद अली, सैयद बहाउद्दीन कादरिया रफाइया, गादीनशीन सैयद असलम, सैयद जैनुल आबेदीन, कादरिया रफाइया का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का आयोजन सैयदपुरा, तुरावा मुहल्ला, हसनजी टेकरा कब्रिस्तान में किया गया।

आंगनवाड़ी की आशा वर्कर बर्कर्स ने बीजेपी कार्यालय के सामने किया विरोध प्रदर्शन

लगाए नोट नहीं तो वोट नहीं के नारे

सूरत। सूरत महानगर पालिका संचालित आँगन वाड़ियो में काम करने वाली आशा वर्कर्स ने अपनी मांग के समर्थन में मंगलवार को विरोध प्रदर्शित कर वर्तमान सरकार पर जम कर प्रहर किये । उधना स्थित बीजीपी कार्यालय के बाहर नारे बाजी कर विरोध प्रदर्शित किया और नोट नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाए। ऐसे नारे लगाने का मकसद मात्र इन आशा वर्करों का इतना था कि उन्होंने पिछले डेढ़ साल से भी अधिक समय से सरकार को अपने वेतन में बढ़ोतरी एवं स्थायी नौकरी की मांग की थी। हालांकि सरकार ने इन आशा वर्करों की मागों को ऑन देखा कर दिया है। सूरत महानगर पालिका संचालित आँगन वाडियों में बतौर आशा वर्कर्स तन तोड़ मेहनत करती है। चाहे पोलियो अभियान हो या आँगन वाड़ी के छोटे बड़े काम हो ये अपने सारा काम सिद्फ्त पूर्वक करती हैं। एक तरफ सरकार जहां पिछले कई सालों से इन आशा वर्कर्स को मानद वेतन ही चुका रही है, वहीं दूसरी और इन की नौकरी भी स्थायी नहीं है। इनके वेतन में से पी एफ की रकम काट लिए जाने से इनके हाथों में तनख्खवाह की मामूली राशि मिलती है। इन सभी मामलों को लेकर आशा वर्करों द्वारा पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से इन आशा वर्करों ने सरकार को अपने वेतन व अन्य सारे मुद्दों को पेश कर इन मसलो पर निकल लेन की मांग कर ही, जिसे सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। आगामी चुनाव का भी बहिस्कार करने की भी धमकी दे दी है।

सूरत। साध्वी प्रज्ञा ठाकूर को महाराष्ट्र के एटीएस द्वारा जबरन गैर कानूनी तरीके से भयंकर शारीरिक एवं मानसिक त्रास दिए जाने के विरोध में मंगलवार को राजस्थान युवा संघ अग्रवाल समाज , माहेश्वरी समाज, विप्र समाज, एवं गौ रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को आवेदन पत्र सोप कर विरोध जताते हुए राष्ट्रपति को मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की।

34 लाख की ठगी कर कोहिनूर मार्केट का दुकानदार फरार

सूरत। रिंगरोड पर स्थित कोहिनूर मार्केट के ठग व्यापारी एम्ब्रोडरी के दो कारखानेदार के पास से उधार में एम्ब्रोडरी वर्क कराने के बाद पैमेन्ट के 34.07 लाख रुपये नहीं चुकाकर दुकान बंद कर फरार हो गया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार रिंगरोड पर स्थित कोहिनूर मार्केट में साडी का व्यापार करनेवाले विजय मंगाजी राजपूत ने पिछले कई वर्षो से कपडा मार्केट तथा एम्ब्रोडरी कारखानेदारों के सामने अपनी अच्छी शाख बनाई थी। जिसके कारण गत फरवरी माह में एम्ब्रोडरी कारखानेदार प्रविणभाई नानुभाई जाडा तथा लालजीभाई वसोया का व्यापारी विजय राजपूत ने संपर्क कर उधार में डायमंड वर्क तथा एम्ब्रोडरी वर्क कराया था। लेकिन उसका बकाया पैमेन्ट 34,07,430 रुपये नही चुकाकर व्यापारी विजय राजपूत फरार हो गया। ठगी का भोग बने दोनों कारखानेदारों ने ठग व्यापारी का संपर्क करने का काफी प्रयास किया लेकिन कोई संपर्क नहीं हो सका। आखिरकार इस संदर्भ में सलाबतपुरा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। कोहिनूर मार्केट में साडी का व्यापार करनेवाले विजय मंगाजी राजपूत ने पिछले कई वर्षो से कपडा मार्केट तथा एम्ब्रोडरी कारखानेदारों के सामने अपनी अच्छी शाख बनाई थी। पुलिस ने ठगी का मामला दर्ज कर आगे की जांच कार्यवाही कर रही है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास,सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं ताप्तीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) E-mail: krantisamay@gmail.com